

बजट 2022-23

प्रलिस के लयल:

बजट और संवैधानकल प्रारवधान, बजट में उल्लखलतल पहल जैसे- पीएम गतशलकृतल, एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा आदल, अमृत काल, आजादी का अमृत महोत्सव ।

मेन्स के लयल:

बजट और संवैधानकल प्रारवधान, बजट 2022 की मुख्य वशलषताएँ ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वतलत मंत्रल ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश कयल । इस बजट के साथ भारत ने [आजादी का अमृत महोत्सव](#) के माध्यम से आजादी के 75 वर्ष पूरे करने को चहलनतल कयल ।

- इसके अलावा बजट अगले 25 वर्षों के लयल एक योजना भी नरुधारतल करता है और उसी अवधलको **अमृत काल** के रूप में संदरभतल करता है ।

बजट 2022 की मुख्य वशलषताएँ:

- वकलस दर:** चालू वर्ष (2021-22) में भारत की आरथकल वृदधल [सकल घरेलू उत्पाद](#) का 9.2% होने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अरथव्यवस्थाओं में सबसे अधकल है ।
- अमृत काल:** भारत ने **अमृत काल** में प्रवेश कयल है, जो भारत@100 की 25 वर्ष लंबी लीडअप योजना है । अमृत काल के दौरान सरकार का उददेश्य नमलनलखलतल लकष्य प्रारपत करना है:
 - सूकषम-आरथकल स्तर की सभी समावेशी कलयाण नीतयों के साथ **'मैक्रो-इकोनॉमकल लेवल ग्रोथ फोकस'** को लागू करना ।
 - डजलटल अरथव्यवस्था और फनलटेक, प्रोदयोगकल सकषम वकलस, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना ।
 - सार्वजनकल पूंजी नवलश के साथ नज्जी नवलश को बढ़ावा देना ।
- अमृत काल का ढाँचा:** चार प्रारथमकलताएँ:
 - पीएम गतशलकृतल
 - समावेशी वकलस
 - उत्पादकता वृदधल और नवलश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई
 - नवलश का वतलतपोषण
- प्रोडकटवलटल लकड इंसेंटवल:** प्रोडकटवलटल लकड इंसेंटवल स्कीम के तहत 14 कषेत्रों में 60 लाख नए रोजगार सृजतल होंगे ।
- बजट में अन्य प्रमुख घोषणाएँ:**
 - रेलवे:** स्थानीय व्यवसायों और आपूरत शृंखलाओं की सहायता के लयल **'वन स्टेशन, वन प्रोडकट'** अवधारणा ।
 - परवतमाला:** यह एक **राष्ट्रीय रोपवे वकलस कार्यक्रम** है, इसे **पीपीपी मोड** पर संपन्न कयल जाना है ।
 - कसलन ड्रोन:** फसल मूल्यांकन, भूमल अभलखों का डजलटललीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्त्वों का छड़कलव ।
 - MSME:** उदयम, ई-शरम, NCS और [असीम पोर्टल](#) को आपस में जोड़ा जाएगा ।
 - कौशल वकलस:** ऑनलाइन प्रशकषण के माध्यम से नागरकों को कौशल प्रदान करने के साथ-साथ आजीवकल हेतु डजलटल पारस्थलतलकल तंत्र (**DESH-Stack e-portal**) शुरू कयल जाएगा ।
 - शलकषा:** पीएम ई-वदलया के 'वन क्लास-वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक वसलतारतल कयल जाएगा ।
 - स्वास्थय:** राष्ट्रीय डजलटल स्वास्थय पारस्थलतलकल तंत्र के लयल एक खुला मंच शुरू कयल जाएगा ।
 - सकषम आँगनवाड़ी (नई पीढी की आँगनवाड़ी):** मशलन शकृतल, मशलन वात्सलय, सकषम आँगनवाड़ी और [पोषण 2.0](#) के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को एकलकृत लाभ ।
 - पीएम-डवलइन:** यह नई योजना प्रवोत्तर कषेत्र के लयल प्रधानमंत्रल वकलस पहल (पीएम-डवलइन) के तहत प्रवोत्तर में बुनयलदी ढाँचे और सामाजकल वकलस परयोजनाओं को नधल देने के लयल शुरू की गई है ।
 - वाइबरेट वललज प्रोग्राम: उत्तरी सीमा पर वरलल आबादी, सीमतल कनेक्टवलटल और बुनयलदी ढाँचे के साथ सीमावर्ती गाँवों के वकलस के लयल

वाइब्रेंट वल्लेज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।

- उदीयमान अवसर: आर्टफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक प्रणालियों और ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा इसका इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स एवं फार्मास्युटिकल्स, हरति व स्वच्छ ऊर्जा आवागमन प्रणालियों में बड़े पैमाने पर सतत् विकास में सहायता करने तथा देश के आधुनिकीकरण की अपार संभावनाएँ हैं।
- GIFT-IFSC: गफिट सटि में वशिव सतरीय वदिशी वशिवदियालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी।
 - अंतरराष्ट्रीय न्याय के तहत वविदों के समय पर नपिटारे के लयि एक **अंतरराष्ट्रीय मध्यसथता केंद्र** स्थापति कयि जाएगा।
- डजिटिल रुपया:** भारतीय रज़िस्व बैंक द्वारा वर्ष 2022-23 से डजिटिल रुपए की शुरुआत की जाएगी।

बजट और संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संवधान के **अनुच्छेद 112** के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वविरण (Annual Financial Statement- AFS) कहा जाता है।
- यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानति प्रापतियों और व्यय का वविरण है (जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।
- बजट में नमिनलखिति बढिओं को शामिल कयि जाता है:**
 - राजस्व और पूंजी प्रापतियों का अनुमान।
 - राजस्व बढाने के तरीके और साधन।
 - व्यय अनुमान।
 - पछिले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्रापतियों और व्यय का वविरण तथा उस वर्ष में कसी भी कमी या अधशिष का कारण।
 - आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, अर्थात् कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरुआत।
- संसद में बजट छह चरणों से गुज़रता है:**
 - बजट की प्रस्तुति।
 - आम चर्चा।
 - वभिगीय समतियों द्वारा जाँच।
 - अनुदान मांगों पर मतदान।
 - वनिथियेग वधियक पारति करना।
 - वतित वधियक पारति करना।
- वतित मंत्रालय के आर्थिक मामलों का वभिग 'बजट डविजन' तैयार करने हेतु ज़मिमेदार केंद्रीय नकिय है।
- स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत कयि गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस